

भारतीय रिज़र्व बैंक का मुद्रा स्वैप: जीएफएसएन में भूमिका और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना

अजेश पलाई द्वारा[^]

केंद्रीय बैंक मुद्रा स्वैप ने वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से वैश्विक वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तपोषण व्यवस्था के माध्यम से। सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क और ब्रिक्स आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था के माध्यम से, आरबीआई जीएफएसएन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान, सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क के तहत रिज़र्व बैंक का स्वैप समर्थन काफी बढ़ गया। भारत की स्वस्थ विदेशी मुद्रा भंडार स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय बैंक मुद्रा स्वैप में भारत के बाह्य वित्तीय सहयोग को और बढ़ावा देने की क्षमता है।

I. भूमिका

वित्तीय और आर्थिक सहयोग देशों के बीच संबंधों का एक अभिन्न अंग रहा है। समय के साथ देशों के बीच आर्थिक संबंध व्यापारिक गतिविधियों से निवेश, सहायता और अनुदान, क्रेडिट और प्रेषण जैसी विकासात्मक सहायता स्वरूप वित्तीय गतिविधियों के व्यापक स्पेक्ट्रम तक विस्तारित हुए हैं। 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वैश्वीकरण ने देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और नया आकार दिया है। विभिन्न वित्तीय संकट की घटनाओं अर्थात् एशियाई वित्तीय संकट 1997-98 और वैश्विक वित्तीय संकट 2008 और उनके प्रतिकूल परिणामों और प्रभाव-विस्तार को कम करने की आवश्यकता ने देशों के बीच, विशेष रूप से क्षेत्रीय स्तर पर वित्तीय और आर्थिक सहयोग को गहरा किया है (हेनिंग, 2011)।

[^] लेखक भारतीय रिज़र्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय विभाग से हैं। लेखक इस आलेख को तैयार करने में प्रोत्साहन और मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए श्री राजन गोयल को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेखक श्रीमती गुंजीत कौर और श्रीमती स्मिता शर्मा के उनके बहुमूल्य इनपुट के लिए आभारी हैं और श्रीजीत एस के योगदान और बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) की टिप्पणियों की सराहना करते हैं। आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

वित्तीय और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में, वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट (जीएफएसएन) एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जीएफएसएन संस्थागत व्यवस्थाओं और तंत्रों के एक समूह के लिए एक छत्र शब्द है जो एक संकट के खिलाफ एहतियाती सहायता प्रदान करता है और मजबूत समष्टिआर्थिक नीतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करते हुए संकट के दौरान चलनिधि सहायता प्रदान करता है। जीएफएसएन में मुख्य रूप से चार चरण हैं: राष्ट्रीय स्तर पर देशों का अपना भंडार, द्विपक्षीय स्तर पर केंद्रीय बैंकों के बीच स्वैप व्यवस्था, क्षेत्रीय स्तर पर देशों के बीच वित्तीय संसाधनों की पूलिंग, जिसे क्षेत्रीय वित्तपोषण व्यवस्था (आरएफए) और मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह एक वैश्विक वित्तीय बैकस्टॉप प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक मुद्रा स्वैप व्यवस्था जीएफएसएन के प्रमुख तत्वों में से एक है, जो मुख्य रूप से द्विपक्षीय स्वैप और आरएफए¹ के माध्यम से कार्य करती है। जीएफएसएन के कुल 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संसाधनों में से, मुद्रा स्वैप व्यवस्था लगभग 2,817 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। स्वैप व्यवस्थाओं में क्रमशः 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान के साथ सार्क² मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क और ब्रिक्स³ आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (सीआरए) शामिल हैं (सारणी 1)।

केंद्रीय बैंक स्वैप लाइनें विशेष रूप से चलनिधि दबाव और भुगतान संतुलन संकट के समय विदेशी मुद्रा वित्त पोषण के मुद्दों को हल करने में मदद करती हैं। जबकि केंद्रीय बैंक घरेलू वित्तीय संस्थानों को स्थानीय मुद्रा चलनिधि से उत्पन्न किसी भी दबाव को दूर करने के लिए स्थानीय मुद्रा प्रदान कर सकते हैं, केंद्रीय बैंक की विदेशी मुद्रा प्रदान करके समर्थन देने की क्षमता उनके पास मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार से बाधित है। इस संदर्भ में, केंद्रीय बैंकों के लिए अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा स्वैप लाइनों तक पहुंच होना महत्वपूर्ण है, जो स्वैप लाइनों की पेशकश करने के इच्छुक हैं।

¹ भले ही आईएमएफ ऋण तकनीकी रूप से मुद्रा स्वैप की प्रकृति में हैं, आईएमएफ इन्हें एक दिशात्मक के रूप में मानता है।

² दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एक संगठन है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के सभी देशों के विकास और प्रगति को बढ़ावा देना है।

³ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह

सारणी 1: प्रमुख केंद्रीय बैंक मुद्रा स्वैप व्यवस्था का एक स्नैपशॉट

क्रम सं.	स्वैप लाइनें/व्यवस्थाएं	मूल्य यूएस \$ बिलियन	संख्या
द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था*			
1	आरक्षित मुद्रा जारीकर्ता @	713	15
2	फेडरल रिज़र्व (अन्य)	450	9
3	पीपुल्स बैंक ऑफ़ चाइना	1,042	34
4	बैंक ऑफ़ जापान	224	6
5	सार्क स्वैप फ्रेमवर्क	2	3
6	अन्य	46	10
आरएफए#			
1	सीएमआईएम	240	-
2	ब्रिक्स सीआरए	100	-
	कुल	2817	

अगस्त 2020 के अंत तक डेटा

@: मूल्य का अनुमान यूएस फेडरल रिज़र्व, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ़ जापान, बैंक ऑफ़ इंग्लैंड, बैंक ऑफ़ कनाडा और स्विस् नेशनल बैंक के बीच स्वैप लाइनों (असीमित) के ऐतिहासिक उपयोग के आधार पर लगाया जाता है।

*स्रोत: रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया की गणनाएं।

#स्रोत: आसियान + 3 समष्टि आर्थिक अनुसंधान कार्यालय (एएमआरओ) और ब्रिक्स सीआरए संधि।

वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) ने केंद्रीय बैंक स्वैप लाइनों के माध्यम से वित्तीय सहयोग को गति प्रदान की। अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने अल्पकालिक डॉलर फंडिंग बाजारों में बढ़े हुए दबावों को दूर करने के लिए जीएफसी के दौरान चयनित केंद्रीय बैंकों तक अमेरिकी डॉलर स्वैप लाइनों का विस्तार किया। ये स्वैप लाइनें चलनिधि संबंधी व्यवधानों के प्रबंधन में सहायक थीं (गोल्डबर्ग एवं अन्य., 2010)। कोविड-19 महामारी के दौरान, यूएस फेडरल रिज़र्व ने केंद्रीय बैंक स्वैप लाइनों के माध्यम से नौ केंद्रीय बैंकों⁴ को चलनिधि प्रदान की। अमेरिकी फेडरल रिज़र्व⁵ सहित छह केंद्रीय बैंकों ने अमेरिकी डॉलर की चलनिधि के प्रावधान को और बढ़ाने के लिए एक समन्वित कार्रवाई की घोषणा की। जीएफसी के बाद, चीन ने व्यापार को बढ़ावा देने और चीनी युआन (सीएनवाई) (सेंट्रल बैंक करेंसी स्वैप ट्रेकर)

⁴ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोरिया, मैक्सिको, सिंगापुर, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के केंद्रीय बैंक।

⁵ बैंक ऑफ़ इंग्लैंड, स्विस् नेशनल बैंक, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ़ कनाडा और बैंक ऑफ़ जापान।

के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 32 प्रतिपक्षों के साथ द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था में प्रवेश किया। आसियान + 3 देशों ने 2010 में चियांग माई पहल बहुपक्षीकरण (सीएमआईएम) की स्थापना एक बहुपक्षीय मुद्रा स्वैप तंत्र के रूप में की ताकि सदस्य देशों के लिए वित्त पोषण की बैकस्टॉप लाइन प्रदान की जा सके⁶। इसी तरह, ब्रिक्स देशों ने संकट के दौरान ब्रिक्स देशों का समर्थन करने के लिए बहुपक्षीय मुद्रा स्वैप तंत्र के रूप में 2015 में सीआरए की स्थापना की⁷। जीएफसी के बाद, भारत ने सार्क क्षेत्र में व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता का समर्थन करने और सार्क देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2012 में सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क लॉन्च किया। कई केंद्रीय बैंक स्वैप व्यवस्थाएं आज स्थायी संस्थागत स्वैप तंत्र में विकसित हो गई हैं (मिंगकी जू, 2016)। इनमें से कुछ स्वैप व्यवस्थाएं अपनी मुद्राओं के अंतरराष्ट्रीयकरण को प्राप्त करने के देशों के बड़े लक्ष्य का एक हिस्सा भी हैं।

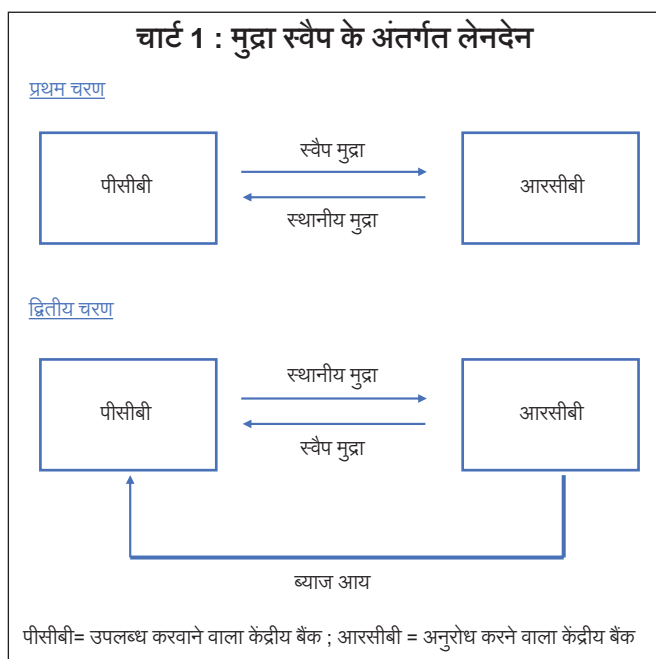
उपरोक्त पृष्ठभूमि के खिलाफ, यह आलेख अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की विभिन्न मुद्रा स्वैप व्यवस्थाओं और इन स्वैप व्यवस्थाओं द्वारा निभाई गई सहायक भूमिका को कवर करने का प्रयास करता है। तदनुसार, शेष आलेख को पांच खंडों में विभाजित किया गया है। खंड II मुद्रा स्वैप व्यवस्था की अवधारणा और उद्देश्यों को प्रस्तुत करता है। खंड III और IV क्रमशः सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क और ब्रिक्स सीआरए को कवर करते हैं। खंड V में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्वैप लाइनों की भूमिका पर चर्चा की गई है, जिसमें खंड VI में समापन टिप्पणी है।

II. मुद्रा स्वैप सुविधा: अवधारणा और उद्देश्य

मुद्रा स्वैप लेनदेन का अर्थ अनुरोध करने वाले केंद्रीय बैंक और सहायता प्रदान करने वाले केंद्रीय बैंक के बीच एक लेनदेन जिसके द्वारा अनुरोध करने वाला केंद्रीय बैंक सहायता प्रदान करने वाले केंद्रीय बैंक से अपनी मुद्रा (स्थानीय मुद्रा) के

⁶ चियांग माई पहल (सीएमआई) 1997-1998 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद शुरू हुई एक द्विपक्षीय स्वैप तंत्र थी।

⁷ जुलाई 2014 में सीआरए संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।



बदले अमेरिकी डॉलर या किसी अन्य विदेशी मुद्रा (स्वैप मुद्रा) की खरीद करता है और बाद की तारीख में स्वैप मुद्रा के बदले स्थानीय मुद्रा की पुनर्खरीद करता है। उस चरण के लेनदेन की विनिमय दर भावी चरणों के लेनदेन पर भी लागू की जाएगी। स्वैप प्राप्तकर्ता केंद्रीय बैंक अपने घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने नियमों, शर्तों और जोखिमों पर स्वैप की गई मुद्रा उधार दे सकता है (चार्ट 1)।

स्वैप तंत्र विदेशी मुद्रा चलनिधि आवश्यकताओं के लिए धन की बैंकस्टॉप लाइन प्रदान करके या भुगतान दबाव के अल्पकालिक संतुलन को संबोधित करके संकट के दौरान वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। जीएफसी और कोविड-19 महामारी के दौरान चुनिंदा देशों के लिए यूएस फेड रिज़र्व की स्वैप लाइनों ने पर्याप्त अमेरिकी डॉलर की चलनिधि सुनिश्चित करने और वित्तीय अस्थिरता जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (पवर्स एवं अन्य., 2021)।

स्वैप आमतौर पर तीन या छह महीने या एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए बढ़ाया जाता है, इसके बाद सहमत शर्तों के अनुसार रोलओवर (नवीनीकरण) किया जाता है। रोलओवर अवधि सहित आहरण के पूरे दौर के बाद, सहायता प्रदान करने वाले देश आम तौर पर सुविधा के लिए बार-बार सहायता प्रदान

करने से बचने के उद्देश्य से अगले आहरण से पहले एक मानक प्रतीक्षा अवधि निर्धारित करते हैं। मुद्रा स्वैप की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि स्वैप मुद्रा और स्थानीय मुद्रा के बीच विनिमय दर आहरण की मूल्य तिथि पर तय की जाती है और उसी समय और भावी लेनदेन दोनों के लिए समान रहती है।

स्वैप तंत्र का कीमत निर्धारण एक महत्वपूर्ण पहलू है। आमतौर पर, स्वैप आहरण के ब्याज को स्वैप आहरण की मुद्रा के आधार पर जमानती एकदिवसीय वित्तपोषण दर (एसओएफआर), यूरो अल्पावधिक दर (ईएसटीआर) लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर)⁸ आदि जैसे वित्तीय बेंचमार्क के साथ बेंचमार्क किया जाता है। चूक जोखिम सहित शामिल कई जोखिमों को कवर करने के लिए इस बेंचमार्क में एक स्प्रेड जोड़ा जाता है। स्वैप की मात्रा और अवधि, प्राप्तकर्ता देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, स्वैप के पुनर्भुगतान के पिछले रिकॉर्ड और अन्य बाह्य दायित्व, चूक की संभावना, परिचालन शुल्क और भू-राजनीतिक विचार के लिए प्रमुख कारक हैं जबकि सहायता प्रदान करने वाला पक्ष स्प्रेड पर निर्णय लेता है। बेंचमार्क आमतौर पर स्वैप के नवीनीकरण के समय पुनर्निर्धारित किया जाता है। स्वैप तंत्र में सामान्यतः चूक होने पर दंडात्मक ब्याज दर का प्रावधान होता है।

स्वैप तंत्र के साथ कुछ जोखिम जुड़े हैं। मुद्रा स्वैप के साथ क्रेडिट जोखिम स्वाभाविक रूप से उच्च है क्योंकि ज्यादातर, संकट/कठिन स्थिति से निपटने के लिए देशों को स्वैप समर्थन दिया जाता है। यदि प्राप्तकर्ता केंद्रीय बैंक चूक करता है, तो सहायता प्रदान करने वाले पक्ष के पास प्राप्तकर्ता देश की मुद्रा के रूप में संपार्श्विक ही रह जाता है। चूक की स्थिति में, प्राप्तकर्ता देश की मुद्रा स्वैप दर के सापेक्ष अपना मूल्य खोने की संभावना है जिस दर पर स्वैप निष्पादित किया गया था। इससे सहायता प्रदान करने वाली पार्टी को नुकसान होगा। इसके कारण, सहायता प्रदान करने वाले केंद्रीय बैंक, जब भी वे उन देशों के साथ स्वैप में प्रवेश करते हैं जिनके पास अत्यधिक अस्थिर मुद्राएं हैं, तो स्वैप लेनदेन अवधि के दौरान स्थानीय मुद्रा के आवधिक पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान करना शामिल होता है।

⁸ लाइबोर से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने से पहले।

एक और चिंता यह है कि चूक होने पर प्राप्तकर्ता देश की मुद्रा के रूप में संपार्श्विक का सहायता प्रदान करने वाला पक्ष कैसे उपयोग करेगा। आम तौर पर, ऐसी चूक स्थिति को हल करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है:

- दोनों देश या तो ऋण चुकौती का पुनर्निर्धारण करके एक पुनर्गठन योजना के लिए सहमत होते हैं या/और देश बकाया दायित्व में कटौती और अन्य छूटों के लिए सहमत हो सकते हैं।
- सहायता प्रदान करने वाले केंद्रीय बैंक अनुरोध करने वाले केंद्रीय बैंक को अनुरोध करने वाले देश के ब्याज, विपणन योग्य सॉवरन ऋण में स्थानीय मुद्रा का निवेश करने का निर्देश दे सकता है। ऐसे तंत्र के माध्यम से प्रदायकर्ता पक्ष ब्याज दर प्राप्त करने में सक्षम होगा।
- प्रदाता देश अनुरोध करने वाले देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार निपटान के लिए स्थानीय मुद्रा शेष का उपयोग कर सकता है। इस शेष राशि का उपयोग प्राप्तकर्ता देश से प्रदाता देश के आयात को वित्तपोषित करने के लिए किया जा सकता है।
- प्रदाता देश बकाया देय राशि के निपटान हेतु रणनीतिक विदेशी निवेश के लिए शेष राशि का उपयोग कर सकता है।

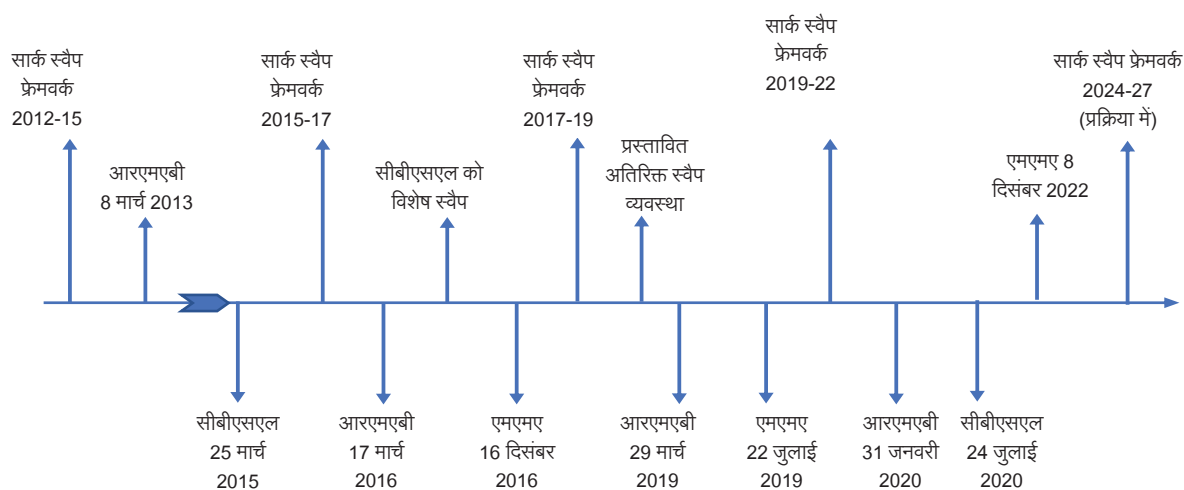
III. सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क

सार्क देशों ने सार्क देशों की अल्पकालिक विदेशी मुद्रा चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक मुद्रा स्वैप तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया और तदनुसार, सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था पर फ्रेमवर्क नवंबर 2012 में लागू हुआ। सार्क मुद्रा स्वैप व्यवस्था अल्पकालिक विदेशी मुद्रा चलनिधि आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए फंडिंग की बैंक-स्टॉप लाइन प्रदान करने में मदद करती है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक दो बिलियन अमरीकी डालर की समग्र निधि के भीतर प्रत्येक सार्क सदस्य देश को अलग-अलग मात्रा के स्वैप की पेशकश करेगा।

फ्रेमवर्क देशों को अमेरिकी डॉलर, यूरो या आईएनआर में स्वैप करने की अनुमति देता है। फ्रेमवर्क को नियमित अंतराल में अपडेट किया जाता है। वर्तमान में, सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था 2019-22 की रूपरेखा तैयार की गई है⁹। आरबीआई ने सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क 2024-27 को अंतिम रूप देने पर काम शुरू कर दिया है। फ्रेमवर्क का विकास और फ्रेमवर्क के तहत हस्ताक्षरित विभिन्न समझौते चार्ट 2 में दिए गए हैं।

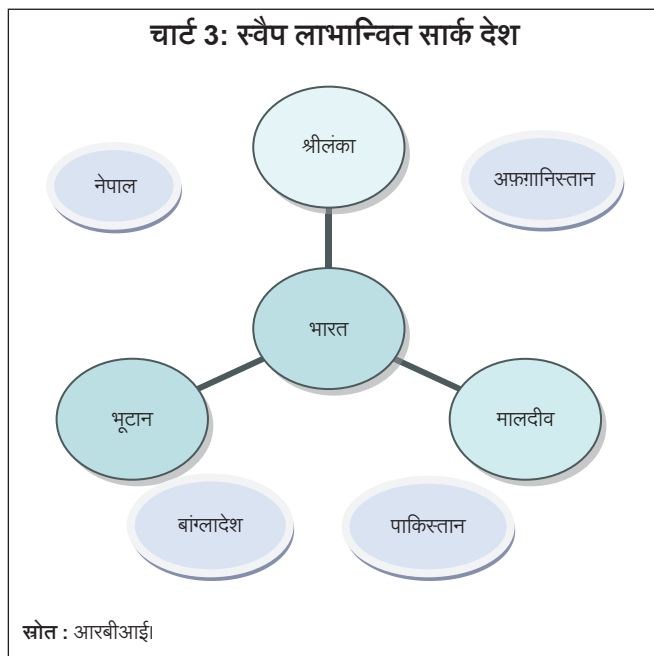
सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क में 'अतिरिक्त स्वैप व्यवस्था' का प्रावधान है जिसे 2018 में एक संशोधन के माध्यम से फ्रेमवर्क में

चार्ट 2: सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क और हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते



आरएमएबी भूटान के रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी को संदर्भित करता है, सीबीएसएल सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को संदर्भित करता है, एमएमए मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को संदर्भित करता है।
स्रोत: आरबीआई

⁹ जिसकी वैधता को 2022 से आगे बढ़ा दिया गया है।



जोड़ा गया था। अतिरिक्त स्वैप व्यवस्था वित्त मंत्री, भारत सरकार को सदस्य देशों (उनकी पात्र सीमाओं से परे) से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के अतिरिक्त स्वैप अनुरोधों को मंजूरी देने का अधिकार देती है। इस फ्रेमवर्क में द्विपक्षीय/बहुपक्षीय विनिमय व्यवस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच सहयोग के साधन के रूप में दो क्रमागत आहरणों के बीच प्रतीक्षा अवधि, द्वितीय रोलओवर प्राप्त करने के लिए आईएमएफ स्टाफ स्तरीय करार की आवश्यकता तथा सूचना का आदान-प्रदान निर्धारित किया गया है।

फ्रेमवर्क आने के बाद से, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने कई बार स्वैप सुविधा का लाभ उठाया। हालांकि, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ने कभी भी इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया (चार्ट 3)।

सारणी 3: कोविड-19 महामारी के दौरान स्वैप समर्थन (2017-19 की तुलना में 2020-22) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

देश	2020-2022 (महामारी का समय) *	2017-2019 (पूर्व-महामारी)
भूटान	800	500
मालदीव	400	200
श्रीलंका	800	400
कुल	2000	1100

स्रोत: आरबीआई, * 2022 के अंत तक।

रिज़र्व बैंक ने सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क की 2012 में स्थापना के बाद से 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल स्वैप समर्थन प्रदान किया है। इनमें से श्रीलंका का हिस्सा 62 प्रतिशत (3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर), भूटान का हिस्सा 26 प्रतिशत (1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और मालदीव का हिस्सा 12 प्रतिशत (0.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है (सारणी 2)।

कोविड-19 महामारी (2020-22) के दौरान, रिज़र्व बैंक ने भूटान, मालदीव और श्रीलंका को पिछले तीन वर्षों 2017-19 के दौरान 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्वैप समर्थन की तुलना में कुल मिलाकर 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वैप सहायता प्रदान की, जिससे इन सदस्य देशों को अपने विदेशी क्षेत्र के दबावों का प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण मदद मिली (सारणी 3)।

IV. ब्रिक्स आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (सीआरए)

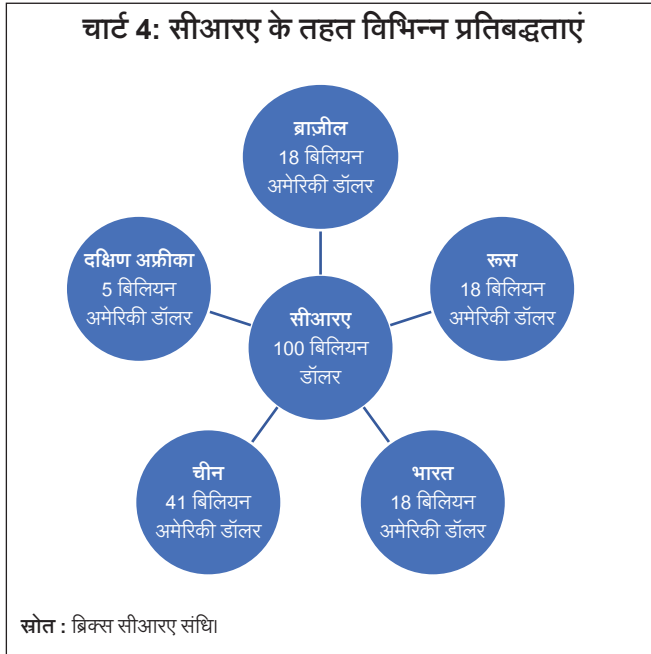
ब्रिक्स सीआरए ब्रिक्स के आर्थिक और वित्तीय सहयोग ट्रैक के तहत एक प्रमुख प्रमुख पहल है। सीआरए एक ऐसा तंत्र है जिसमें ब्रिक्स देशों ने पारस्परिक स्वैप समर्थन प्रदान करके भुगतान संकट के अल्पकालिक संतुलन को दूर करने में मदद करने के लिए एक स्व-प्रबंधित आकस्मिक आरक्षित पूल स्थापित किया है। ब्रिक्स देश सीआरए के तहत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल संसाधन के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसमें चार्ट 4 में प्रत्येक की प्रतिबद्धताओं को दर्शाया गया है।

सारणी 2: सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क के तहत कुल स्वैप समर्थन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

देश	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
भूटान	---	100	100	100	300	200	200	400	200	1600
मालदीव	---	---	100	---	100	150	250	---	100	700
श्रीलंका*	1500 (1100+400)	1100 (700+400)	400	---	---	400	---	400	---	3800
कुल	1500	1200	600	100	400	750	450	800	300	6100

स्रोत: आरबीआई; *इसमें सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क के अतिरिक्त 2015-16 के दौरान 1100 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समर्थन शामिल है।

चार्ट 4: सीआरए के तहत विभिन्न प्रतिबद्धताएं

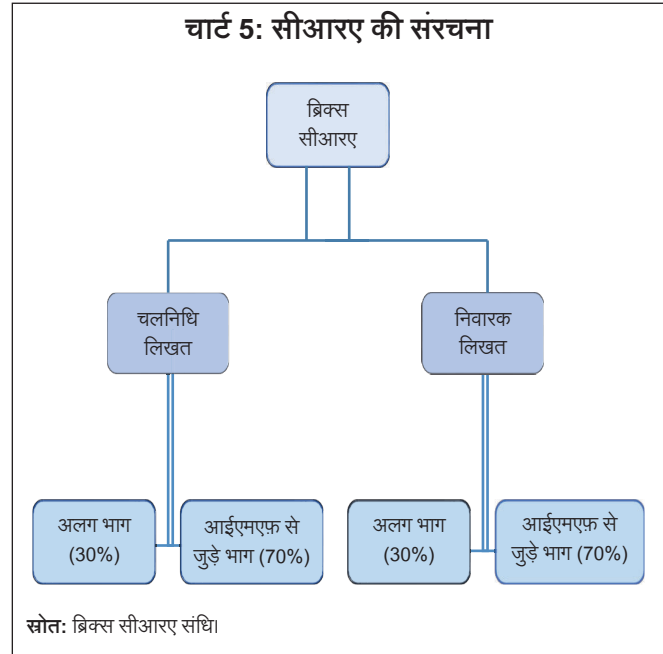


सीआरए के मुख्य रूप से दो साधन हैं, चलनिधि और एहतियाती साधन। एक चलनिधि साधन भुगतान संतुलन के दबाव के जवाब में तत्काल चलनिधि सहायता प्रदान करेगा। एक एहतियाती साधन भुगतान संतुलन के संभावित दबाव को देखते हुए सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता है। इन दोनों साधनों में डी-लिंकड और आईएमएफ लिंकड भाग है। डी-लिंकड हिस्से के तहत, देशों के पास प्रत्येक पक्ष के लिए अधिकतम पहुंच के 30 प्रतिशत के बराबर अभिगम है। आईएमएफ लिंकड हिस्से के तहत, देशों के पास अधिकतम अभिगम के शेष 70 प्रतिशत तक अभिगम है (चार्ट 5)।

सारणी 4: सीआरए के तहत देशवार अभिगम				
	प्रतिबद्धता (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	गुणक	कुल अभिगम (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	अलग व्यवस्था के साथ अभिगम सीमा (बिलियन अमेरिकी डॉलर)
ब्राज़ील	18.0	1.0	18.0	5.4
रूस	18.0	1.0	18.0	5.4
चीन	41.0	0.5	20.5	6.15
भारत	18.0	1.0	18.0	5.4
दक्षिण अफ्रीका	5.0	2.0	10.0	3.0
कुल	100.0			

स्रोत: ब्रिक्स सीआरए संधि।

चार्ट 5: सीआरए की संरचना



प्रतिबद्धता राशि से अभिगम राशि का निर्धारण करने के लिए गुणक मान दक्षिण अफ्रीका (2) के लिए उच्चतम गुणक मूल्य और चीन के लिए सबसे कम (0.5) के साथ भिन्न होते हैं। ब्राज़ील, रूस और भारत का गुणक मूल्य एक (1) है। देशवार अभिगम राशि सारणी 4 में प्रस्तुत की गई है।

सीआरए के तहत परिपक्वता, नवीकरण की संख्या और कुल समर्थन अवधि साधनों के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है। यह डी-लिंकड और आईएमएफ-लिंकड भाग के बीच भी भिन्न होती है, जिसमें स्वैप समर्थन की न्यूनतम अवधि छह महीने और अधिकतम तीन वर्ष होती है (सारणी 5)।

सारणी 5: लिखतों के तहत परिपक्वता और अवधि

लिखत	भाग	अवधि/ परिपक्वता	नवीनीकरण की संख्या	सहायक अवधि
पूर्वोपाय लिखत	अलग अभिगम	6 माह	3	2 वर्ष
	अलग आहरण	6 माह	-	6 माह
	आईएमएफ से जुड़े अभिगम	1 वर्ष	2	3 वर्ष
	आईएमएफ से जुड़े आहरण	1 वर्ष	-	1 वर्ष
चलनिधि लिखत	अलग आहरण	6 माह	3	2. वर्ष
	आईएमएफ से जुड़े आहरण	1 वर्ष	2	3. वर्ष

स्रोत: ब्रिक्स सीआरए संधि।

तालिका 6: ब्रिक्स सीआरए की विशेषताएं

संख्या	लक्षण	विवरण
1	अभिशासन	सीआरए के तहत एक गवर्निंग काउंसिल (जीसी) का गठन किया जाता है, जो उच्च स्तरीय और कार्यनीतिक निर्णयों के लिए जिम्मेदार होती है। स्थायी समिति (एससी) कार्यकारी स्तर और परिचालन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है।
2	नकदीकरण	यह एक प्रदान करने वाले देश को अनुरोध करने वाली पार्टी से स्वैप समर्थन के बाद भी समर्थन वापस लेने में सक्षम करेगा। प्रदान करने वाली पार्टी नकदीकरण का अनुरोध कर सकती है यदि वह उसके भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा आरक्षित स्थिति या युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसी अप्रत्याशित घटना से समर्थित हो।
3	ऑफ्ट-आउट	यह किसी भी पार्टी को एक लिखत के तहत सहायता प्रदान करने से अलग रहने की अनुमति देगा।
4	नवीनता	अनुरोध करने वाला पक्ष, चूक के समय, अपने बकाया दायित्वों के नवीकरण के लिए सहमत होगी जिसमें विपणन योग्य ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना शामिल हो सकता है जो अनुरोध करने वाले पक्ष के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होगा।

स्रोत: ब्रिक्स सीआरए संधि

सीआरए की अन्य प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में सारणी 6 में उल्लेख किया गया है।

सीआरए एससी ने दिसंबर 2017 में सीआरए की परिचालन तत्परता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए टेस्ट रन आयोजित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने अब तक विभिन्न जटिलताओं और परिदृश्यों को शामिल करते हुए छह टेस्ट रन सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं (सारणी 7)।

एक स्वैप तंत्र के रूप में, ब्रिक्स सीआरए में सीएमआईएम और सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क के साथ बहुत सारी समानताएं हैं। उनके डिजाइन, संरचना और परिचालन में उनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं (सारणी 8)।

सार्क स्वैप फ्रेमवर्क और सीआरए के अलावा, रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ जापान के साथ 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की राशि के लिए एक मुद्रा स्वैप व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए।

V. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना

केंद्रीय बैंक स्वैप लाइनें देशों के बीच/बीच वित्तीय सहयोग को गहरा करने में मदद करती हैं। केंद्रीय बैंक स्वैप सॉवरेन राष्ट्रों के बीच समझौते हैं जो संबंधित सरकारों की सहमति और अनुमोदन के साथ अपने केंद्रीय बैंकों के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं। अनुरोध करने वाले पक्ष की सॉवरेन सरकार से गारंटी, पूरी स्वैप राशि को कवर करना आम तौर पर स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक शर्त है। अनुरोध करने वाले देश की सरकार को यह भी प्रमाणित करने की आवश्यकता

सारणी 7: सीआरए के तहत परीक्षण किए गए विभिन्न तत्व

CRA Test Run	समन्वयकर्ता	अनुरोधकर्ता पक्ष	तत्वों का परीक्षण
2018	दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक	ब्राजील सेंट्रल बैंक	➤ चलनिधि लिखतों के डी-लिंक भाग
2019	ब्राजील सेंट्रल बैंक	बैंक ऑफ रशिया	➤ निवारक लिखत का डी-लिंक भाग ➤ नकदीकरण
2020	बैंक ऑफ रशिया	आरबीआई	➤ निवारक लिखत का डी-लिंक भाग ➤ पूर्व-अदायगी
2021	आरबीआई	पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना	➤ चलनिधि लिखतों के आईएमएफ-लिंक भाग ➤ ऑफ्ट-आउट ➤ चुकोती में देरी
2022	पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना	दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक	➤ चलनिधि लिखतों के आईएमएफ-लिंक भाग ➤ वैकल्पिक मुद्राओं में भुगतान
2023	दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक	ब्राजील सेंट्रल बैंक	➤ चलनिधि लिखतों के डी-लिंक भाग ➤ वैकल्पिक मुद्राओं में भुगतान ➤ दो ऑफ्ट-आउट अनुरोध

स्रोत: आरबीआई

सारणी 8: ब्रिक्स सीआरए की सीएमआईएम तथा सार्क स्वैप फ्रेमवर्क के साथ तुलना

क्रम सं.	ब्रिक्स सीआरए	सीएमआईएम	सार्क स्वैप फ्रेमवर्क
1.	एक बहुपक्षीय मुद्रा विनियम तंत्र जिसमें सभी ब्रिक्स देशों द्वारा स्वैप प्रतिबद्धता साझा की जाती है।	आसियान प्लस 3 देशों के बीच एक बहुपक्षीय मुद्रा विनियम तंत्र, जिसमें सभी सदस्य देशों द्वारा स्वैप प्रतिबद्धता साझा की जाती है।	सभी सार्क देशों के लिए लागू एक सामान्य ढांचे के साथ एक द्विपक्षीय विनियम तंत्र, और स्वैप प्रतिबद्धता पूरी तरह से भारत द्वारा वहन की जाती है।
2.	भारत सीआरए के तहत अनुदान देने वाला पक्ष और अनुरोध करने वाला पक्ष दोनों हो सकता है।	कोई भी आसियान प्लस 3 देश दोनों अनुदान करने वाले पक्ष के साथ-साथ अनुरोध करने वाले पक्ष भी हो सकते हैं।	भारत सहायता प्रदान करने वाला एकमात्र पक्ष है, अन्य इच्छुक सार्क देश अनुरोधकर्ता पक्ष हैं।
3.	कुल कोष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।	कुल कोष 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।	कुल कोष 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
4.	विनियम आहरण केवल अमेरिकी डॉलर में उपलब्ध है।	विनियम आहरण अमेरिकी डॉलर, सीएनवाई और आसियान प्लस के तीन देशों की अन्य स्थानीय मुद्राओं में उपलब्ध हैं।	विनियम आहरण अमेरिकी डॉलर, यूरो और भारतीय रुपए में उपलब्ध है।
5.	भविष्य के संकट से निपटने के लिए एहतियाती लिखत का प्रावधान उपलब्ध है।	भविष्य के संकट से निपटने के लिए एहतियाती लिखत प्रावधान उपलब्ध है।	कोई एहतियाती लिखत उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: आरबीआई, एएमआरओ और सीआरए संधि।

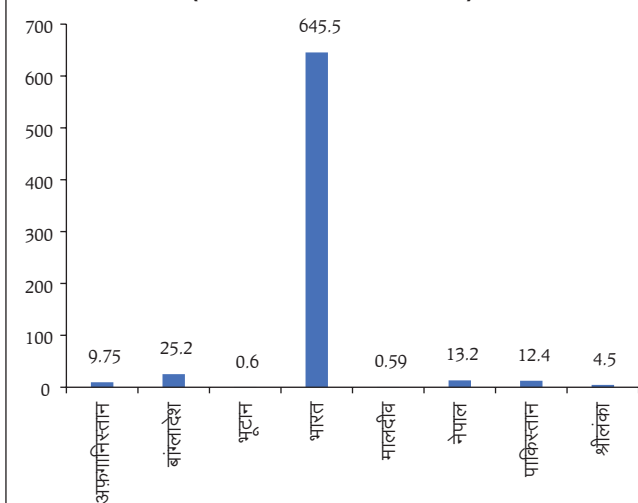
है कि वे कोई भुगतान प्रतिबंध नहीं लगाएंगे जो केंद्रीय बैंकों के स्वैप के बकाया दायित्व के पुनर्भुगतान पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। संकट के समय में किसी देश को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करके, स्वैप तंत्र वित्तीय सहयोग का एक मजबूत चैनल प्रदान करता है।

ऐसे कई अवसर आए हैं जब भारत ने आकस्मिक स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए सार्क देशों की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क के अंतर्गत उनकी पात्र सीमाओं और अवधि से अधिक स्वैप सहायता प्रदान की है। रिज़र्व बैंक ने सीबीएसएल को दो विशेष जुलाई 2015 और मार्च 2016 में क्रमशः 1100 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता के साथ मुद्रा स्वैप सुविधाएं प्रदान कीं, जो सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क से बाहर थीं। श्रीलंका के साथ भारत के मजबूत द्विपक्षीय समझौतों और आर्थिक संबंधों के संदर्भ में अल्पकालिक चलनिधि प्रबंधन के लिए ये विशेष स्वैप समर्थन प्रदान किए जाते हैं। देशों द्वारा अतिरिक्त स्वैप सहायता के अनुरोध का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त स्वैप व्यवस्था के प्रावधान को कई बार लागू किया गया है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार की सुविधा ने भारत को इन स्वैप समर्थनों का विस्तार करने में मदद की (चार्ट 6)।

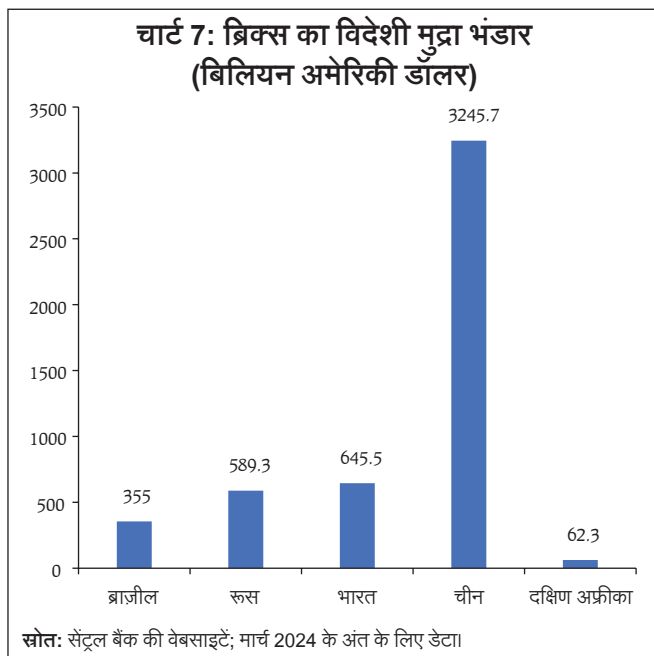
सीआरए में ब्रिक्स देशों का योगदान उनकी विदेशी मुद्रा की स्थिति को दर्शाता है (चार्ट 7)। भले ही अब तक सीआरए के तहत स्वैप का लाभ कभी नहीं उठाया गया है, सीआरए के तहत विभिन्न कार्यों ने ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग को

तेज करने में मदद की। ब्रिक्स सीआरए के हिस्से के रूप में, ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने 2016 में भारत के ब्रिक्स में अध्यक्षता के दौरान समष्टि-आर्थिक सूचना के आदान-प्रदान की एक प्रणाली (सेमी) विकसित की, जो वास्तविक, राजकोषीय और बाह्य क्षेत्रों, पूंजी बाजार और वित्तीय सुदृढ़ता को कवर करने वाले साठ व्यापक आर्थिक संकेतकों का एक टेम्पलेट है। वर्ष 2020 में रूसी अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने सीआरए के हिस्से के रूप में ब्रिक्स आर्थिक बुलेटिन का वार्षिक संस्करण तैयार किया, जिसका विषय 'कोविड-19 महामारी' था। बुलेटिन में ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति, संचित जोखिम, कोविड-

चार्ट 6: सार्क देशों के विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन अमेरिकी डॉलर)



स्रोत: सेंट्रल बैंक की वेबसाइट; फरवरी/मार्च 2024 के अंत के लिए डेटा; दिसंबर 2023 के अंत के लिए भूटान का डेटा; वर्ष 2020 के अंत के लिए अफगानिस्तान का डेटा।



19 संकट के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए नीतिगत उपायों, भावी दृष्टिकोण और सहयोग के नए क्षेत्रों पर अवलोकन प्रदान किया गया। ब्रिक्स आर्थिक बुलेटिन 2021 'नेविगेटिंग द ऑनगोइंग पैडेमिक: द ब्रिक्स एक्सपीरियंस ऑफ रेजिलिएशन एंड रिकवरी' विषय पर केंद्रित रहा। वर्ष 2022 में चीन के ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने ब्रिक्स आर्थिक बुलेटिन (ब्रिक्स आर्थिक बुलेटिन) की वार्षिक कवायद जारी रखी। वर्ष 2021 में 'कोविड-19: ब्रिक्स के भुगतान संतुलन के लिये विपरीत और अनुकूल परिस्थितियाँ' विषय पर आयोजित पहले ब्रिक्स सहयोगात्मक अध्ययन ने चालू खाता शेष के साथ-साथ ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी प्रवाह पर महामारी के प्रभाव की जाँच की।

संकट की स्थितियों का अनुकरण करके कई सीआरए टेस्टों के संचालन ने ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के बीच जुड़ाव को गहरा कर दिया है। सीआरए तकनीकी समूह सीआरए में शामिल विभिन्न तकनीकी मुद्दों की जांच करता है और इन मुद्दों के समाधान के लिए उपाय करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक निकाय सीआरए जीसी वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करता है और सीआरए के संबंध में कार्यनीतिक निर्णय

लेता है। इसी तरह, ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के उप गवर्नरों के स्तर पर सीआरए एससी, सीआरए के संबंध में किसी भी परिचालन मुद्दों पर निर्णय लेता है। सीआरए के माध्यम से आदान-प्रदान के इन कई स्तरों ने ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ किया है।

भारत-जापान स्वैप व्यवस्था भारत और जापान के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को दर्शाती है जिसने इन दोनों देशों के बीच वित्तीय जुड़ाव को गहरा करने में मदद की है।

हाल के वर्षों में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में काफी वृद्धि हुई है। जब भारत ने 2012 में सार्क स्वैप फ्रेमवर्क का गठन किया, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 300 बिलियन डॉलर था, जबकि आज यह दोगुना से अधिक है। इसने भारत को देशों को अधिक स्वैप समर्थन देने के लिए पर्याप्तता और लीवरेज प्रदान किया है।

वर्तमान में, रिज़र्व बैंक सार्क स्वैप फ्रेमवर्क के तहत आईएनआर स्वैप आहरण को विभिन्न रियायतें प्रदान करता है, ताकि आईएनआर में स्वैप के आहरण को प्रोत्साहित किया जा सके, जैसे लगातार दो आहरणों के बीच कम प्रतीक्षा अवधि और दूसरे स्वैप रोलओवर का लाभ उठाने के लिए शर्तों की छूट के संदर्भ में।

VI. निष्कर्ष

केंद्रीय बैंक मुद्रा स्वैप जीएफएसएन संरचना का एक अभिन्न अंग हैं। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर स्वैप लाइनों ने देशों को अपनी आकस्मिक विदेशी मुद्रा चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक विकल्प प्रदान किए हैं। स्वैप व्यवस्था ने महामारी के दौरान देशों को उनके बाहरी क्षेत्र के दबावों का प्रबंधन करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे देखें तो, आईएमएफ और आरएफए सहित जीएफएसएन के विभिन्न स्तंभों के बीच सहयोग को जीएफएसएन प्रणाली को अधिक मजबूत और गतिशील बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। विदेशी मुद्रा भंडार के पर्याप्त स्तर द्वारा समर्थित, केंद्रीय बैंक मुद्रा स्वैप में भारत के बाह्य वित्तीय सहयोग को मजबूत और गहरा करने की उच्च क्षमता है।

संदर्भ

Ball, M., Clarke, A., and Noone, C. (2020). The Global Financial Safety Net and Australia. Reserve Bank of Australia Bulletin, September.

Central Bank Currency Swaps Tracker, <https://www.cfr.org/article/central-bank-currency-swaps-tracker>

Goldberg, L., Kennedy, C., and Miu, J. (2010). Central Bank Dollar Swap Lines And Overseas Dollar Funding Costs. *NBER Working Paper* 15763.

Henning, C.R. (2011). Economic Crises and Institutions for Regional Economic Cooperation. Asian Development Bank.

International Monetary Fund. (2017). Discussion Paper on 'The Treatment of Currency Swaps Between Central Banks'.

Mingqi, Xu. (2016). Central Bank Currency Swaps and Their Implications to the International Financial Reform. *China Quarterly of International Strategic Studies*, Vol. 2, No. 1, 135–152.

Perks, M., Rao, Y., Shin J., and Tokuoka, K. (2021). Evolution of Bilateral Swap Lines. *International Monetary Fund Working Paper* 21/210.